[2017] 5 एस. सी. आर. 87

मेसर्स सी. आर. आर. सी. कॉर्पोरेशन लिमिटेड

बनाम

मेट्रो लिंक एक्सप्रेस फॉर गांधीनगर एंड अहमदाबाद (मेगा) कंपनी लिमिटेड

(सिविल अपील संख्या 12065/2016)

15 मई, 2017

[दीपक मिश्रा और अमितावा रॉय, जे. जे.]

अनुबंधः

किसी परियोजना के लिए निविदाएं/बोलियां आमंत्रित करने वाली प्रत्यर्थी कंपनी-बोलीदाताओं की 'तकनीकी बोलियां' और 'मूल्य बोलियां' खोलने से पहले पात्रता और योग्यता मानदंड का निर्धारण-अपीलकर्ता-निगम की बोली ने निविदा दस्तावेजों की धारा 3 के खंड 2.4 के संदर्भ में अनुभव में कमी के आधार पर इसे आगे की भागीदारी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया-क्या अपीलकर्ता-निगम, खंड 2.4 द्वारा निर्धारित अनुभव मानदंड को पूरा करने के लिए, प्रारंभिक बोली में अर्हता प्राप्त करने के लिए अपनी सहायक कंपनियों (संयुक्त उद्यम या संघ के घटक नहीं होने के कारण) के अनुभव का उपयोग कर सकता है-आयोजितः बोलीदाताओं को दिए गए निर्देशों की धारा 1 के खंड 4.1 के अनुसार, एक बोलीदाता एकल इकाई या इस तरह के संयोजन हो सकता है।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. बोलीदाताओं को दिए गए निर्देशों की धारा 1 के खंड 4 के एक सादे अध्ययन से पता चलता है कि एक बोलीदाता एक एकल इकाई या ऐसी संस्थाओं का एक संयोजन हो सकता है जो एक मौजूदा समझौते के तहत एक संयुक्त उद्यम या संघ के रूप में या एक आशय पत्र द्वारा समर्थित इस तरह के समझौते में प्रवेश करने के इरादे से हो सकता है। इस प्रकार एक एकल इकाई को सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए एक वैध बोलीदाता माना गया है। [पैरा 34) (111-ए)

2. एक एकल इकाई में निश्चित रूप से ऐसी सरकारी स्वामित्व वाली इकाई के साथ-साथ इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां शामिल होंगी। यह एक सार्वजनिक परियोजना के समय पर और गुणवत्ता निष्पादन के समग्र हित में प्रतिस्पर्धी मूल्य और क्षमताओं के साथ संस्थाओं की व्यापक आधारित भागीदारी की अन्यथा अनिवार्य सुविधा की कसौटी पर अधिक है। परियोजना के परिमाण के साथ-साथ उसके गुणवत्ता निष्पादन के लिए आवश्यक अनुभव और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए, पहली जगह पर, किसी सरकारी स्वामित्व वाली इकाई को उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के साथ इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य होने का अनुमान लगाने का कोई औचित्य नहीं है। [पैरा 35] [111-बी-डी]

3. वर्तमान निविदा प्रक्रिया में एकल इकाई बोलीदाता के रूप में अपीलकर्ता निगम की स्थिति और अधिकार, जैसा कि पहले से ही टीटागढ़ फ़ायरमा एडलर एस. पी. ए. मामले के संघ में निर्णय लिया गया है, सरल तर्क और सादृश्य के आधार पर भी उपलब्ध होंगे। खंड 4 में "सरकारी स्वामित्व वाली इकाई" शब्दों की अनुपस्थिति, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का कोई परिणाम नहीं है। टीटागढ़ फ़ायरमा एडलर एस. पी. ए. मामले के संघ में शामिल खंड 4 में, "सरकारी स्वामित्व वाली इकाई" को एक

संयुक्त उद्यम के रूप में "निजी इकाई" और "ऐसी संस्थाओं के किसी भी संयोजन" के विपरीत बोली लगाने वालों में से एक के रूप में माना गया था। वर्तमान खंड 4.1 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "एकल इकाई" होने के कारण, स्पष्ट रूप से, इसमें एक निजी के साथ-साथ एक सरकारी स्वामित्व वाली इकाई भी शामिल है। एकल इकाई के रूप में परिकल्पित इकाई इस प्रकार एक संयुक्त उद्यम या संघ के रूप में किसी भी संयोजन या गठन से स्वतंत्र है और इस प्रकार एक अभिन्न और समग्र समग्र के रूप में कल्पना की जाती है। इस तरह के तार्किक आधार में, अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के साथ एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी को एकल इकाई के रूप में समझा जाना चाहिए, जो निविदा शर्तों के खंड 4 के संदर्भ में बोली लगाने के लिए पात्र है और इसे एकल, सुसंगत और सजातीय अस्तित्व के रूप में माना जाना चाहिए, न कि एक असंबद्ध गठन के रूप में। [पैरा 37] [111-जी, एच; 112-ए-डी]

4. विवाद से संबंधित प्रश्न और स्पष्टीकरण, किसी भी तरह से प्रतिवादी की याचिका की पुष्टि नहीं करते हैं। अपीलार्थी की बोली की अस्वीकृति का आधार मुख्य रूप से क्रम संख्या 50 पर प्रश्न का स्पष्टीकरण है। यह पेटेंट है कि यह एक सहायक कंपनी द्वारा अपने लाभ के लिए मूल कंपनी/समूह कंपनियों के अनुभव को उसके संबंध में योग्यता की आवश्यकता को पूरा करने की अनुमति देने के लिए किए गए प्रश्न के जवाब में था। इस संदर्भ में यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि सहायक कंपनी/समूह कंपनियाँ मूल कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम/संघ के सदस्य के रूप में बोली लगा सकती हैं, ताकि मूल/समूह कंपनी के अनुभव को ध्यान में रखा जा सके। इस स्पष्टीकरण का विस्तार किया गया और अपीलार्थी के खंड संख्या 2.4.1,2.4.2 (ए), 2.4.2 (बी) और 2.4.2 (सी) की तुलना में इसे इस आधार पर अयोग्य घोषित करने के लिए लागू किया गया कि अकेले खड़े होने के आधार पर, यह निर्धारित अनुभव में कमी थी और यह कि यह अपनी सहायक कंपनियों के अनुभव का लाभ नहीं उठा सकता था। इस स्पष्टीकरण

का इसके मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है और इसलिए, इस आधार पर इसे अयोग्य घोषित करने का निर्णय स्पष्ट रूप से मनमाना, भेदभावपूर्ण, अनुचित, अतार्किक और गैर-पारदर्शी है, इस प्रकार इसे अपरिवर्तनीय रूप से अवैध, अन्यायपूर्ण और अनुचित बनाता है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत और उच्च न्यायालय द्वारा प्रासंगिक ढांचे में समर्थित व्याख्या इस प्रकार स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य और बेतुकी है। [पैरा 38] [113-ए; 112-डी-एच]

5. अपीलार्थी निगम ने न केवल मांगे गए स्पष्टीकरणों पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, बल्कि सरकार के स्वामित्व वाले निगम के रूप में इसकी स्थिति पर प्रतिवादी द्वारा किसी भी तरह से विवाद नहीं किया गया है। इसके अलावा, सभी परिणामी कानूनी निहितार्थों के साथ इसकी सहायक कंपनियों के लिए इसकी प्रदर्शित संरचनात्मक अखंडता और कार्यात्मक एकता के सामने, प्रतिवादी की यह आशंका कि अपीलार्थी की सहायक कंपनियां, यदि आवश्यकता पड़ी तो, परियोजना के निष्पादन के लिए उपलब्ध नहीं होंगी, अनुबंध का एक पक्ष नहीं होने के नाते, कम से कम कहने के लिए, अटकलबाजी, निराधार, दूरगामी और तर्क और तर्क में अभाव है। क्या अपीलार्थी की सहायक कंपनियां कार्य के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होंगी, यह अपीलार्थी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की संरचनात्मक विशिष्टताओं और कार्यात्मक गतिशीलता से स्पष्ट होता है, जैसा कि टीटागढ़ फ़ायरमा एडलर एस. पी. ए. मामले के कंसोर्टियम में सकारात्मक रूप से देखा गया है और इसमें आगे विस्तार की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 39) [113-बी-डी]

6. इसलिए, खंड 2.4 के संदर्भ में अनुभव की कमी के आधार पर अपीलार्थी की आक्षेपित अयोग्यता कानून में और तथ्यों के घोर रूप से अवैध, मनमाना और विकृत होने पर टिकाऊ नहीं है। [पैरा 40) [113-ई)

*टीटागढ़ फ़ायरमा एडलर एस. पी. ए.-टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड बनाम नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2017) 7 एस. सी. सी. 486-के संघ पर भरोसा किया गया।

न्यू होराइजन्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1995) 1 एस. सी. सी. 478: [1994] 5 पूरक एससीआर 310; एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्यः 2016 (8) स्केल 765: (2016) 3 एससीआर 551; तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सीएसईपीडीआई-ट्रिश कंसोर्टियम 2016 (10) स्केल 69: [2016] 7 एससीआर 495; मोंटेकार्लो लिमिटेड बनाम एनटीपीसी लिमिटेड 2016 (10) स्केल 50: [2016) 8 एससीआर 224; कोर प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम बिहार राज्य 2011 (59) बीएलजेआर 183; रोहडे और श्वार्ज जीएमबीएच एंड कंपनी केजी. बनाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य (2014) 207 डी. एल. टी. 1-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1994) 5 पूरक एस. सी. आर. 310 पैरा 22 संदर्भित

[2016] 3 एस. सी. आर. 551 पैरा 23 संदर्भित

(2016) 7 एस. सी. आर. 495 पैरा 23 संदर्भित

[2016) 8 एस. सी. आर. 224 पैरा 23 संदर्भित

2011 (59) बी. एल. जे. आर. 183 पैरा 23 संदर्भित

(2014) 207 डी. एल. टी. 1 पैरा 23 संदर्भित

(2017) 7 एस सी सी 486 पैरा 24 संदर्भित

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 12065/2016

2016 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 18439 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 18.11.2016 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से सी. ए. सुंदरम, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रभजीत जौहर, गालव शर्मा, सुश्री अनुपमा कौल, एम. पी. सिंह, एस. एस. जौहर, अधिवक्ता।

मुकुल रोहतगी, ए. जी., महेश अग्रवाल, अभिनव अग्रवाल, मुंजाल भट्ट, ऋषभ पारिख, ई. सी. अग्रवाल, प्रतिवादी के वकील।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

अमितावा रॉय, जे. -

1. मतभेद वैश्विक भागीदारी के साथ एक प्रतिष्ठित परियोजना के रूप में निविदा शर्तों में संलग्न एक पात्रता मानदंड की व्याख्या के इर्द-गिर्द केंद्रित है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी द्वारा 2016 के विशेष सिविल आवेदन 18439 में दिए गए 18.11.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय द्वारा समर्थित प्रासंगिक योग्यता मानदंड के बारे में अपनी धारणा के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है, इस प्रकार इसे निवारण के लिए इस न्यायालय में भेजा जाता है।

2. हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी. ए. सुंदरम और प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी को सुना है।

3. यद्यपि निवेदन किए गए तथ्यों में विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनका उठाए गए मुद्दे पर सीधा असर है, केवल उनका ही उल्लेख किया जाएगा।

4. अपीलकर्ता-निगम ने खुद को मेसर्स सी. एस. आर. निगम लिमिटेड और मेसर्स सी. एन. आर. निगम लिमिटेड के समामेलन के रूप में पेश किया है, दोनों ने अपने पूर्ण नियंत्रण के तहत कई सहायक कंपनियों के साथ रेलवे रोलिंग स्टॉक, ई. एम. यू., मेट्रो कोच, शहरी रेल पारगमन वाहन, इंजीनियरिंग मशीनरी, परामर्श सेवाओं आदि के लिए अनुसंधान और विकास डिजाइन, निर्माण, मरम्मत, बिक्री, पट्टे और तकनीकी सेवाओं को शामिल करते हुए अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के साथ सबसे पूर्ण उत्पाद लाइनों और अग्रणी प्रौद्योगिकियों के साथ रेल परिवहन उपकरणों के दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने आपूर्तिकर्ता होने का दावा किया है। 09.03.2015 पर, ये दो इकाइयाँ अर्थात्; मेसर्स सी. एस. आर. निगम लिमिटेड और मेसर्स सी. एन. आर. निगम लिमिटेड का संबंधित राज्य प्राधिकरणों की मंजूरी प्राप्त करने के बाद विलय हो गया, जिसके परिणामस्वरूप, इन दोनों एकीकृत निगमों की सभी परिसंपत्तियां, देनदारियों, व्यवसायों, योग्यताओं, कर्मचारियों, अनुबंधों के साथ-साथ सभी अधिकार और दायित्व अपीलकर्ता-निगम को स्थानांतरित कर दिए गए 01.06.2015 से । इस तरह के एकीकरण के बाद, अपीलकर्ता-निगम एक संयुक्त स्टॉक लिमिटेड कंपनी के रूप में सीमित देयता के साथ चीन जनवादी गणराज्य में निगमित था और चीनी केंद्र सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में था। इस तरह के विलय के परिणामस्वरूप, मेसर्स सी. एस. आर. की सहायक कंपनियां। निगम लिमिटेड और मिस सी. एन. आर. निगम लिमिटेड, अपीलार्थी-निगम की सहायक कंपनी बन गई और उनके नाम भी बदल दिए गए।

अपीलार्थी के अनुसार, इसके बाद इसने सफलतापूर्वक भाग लिया और अपनी सहायक कंपनियों के अनुभव के आधार पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों से सम्मानित किया गया।

5. 15.01.2016 पर, प्रत्यर्थी कंपनी (जिसे इसके बाद "मेगा" के रूप में भी संदर्भित किया जाएगा) ने "डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, 96 संख्या में मानक गेज कारों को चालू करने और कर्मियों के प्रशिक्षण" के लिए निविदाएं/बोलियां आमंत्रित कीं और सभी संभावित बोलीदाताओं को 12.03.2016 पर आमंत्रित करने के लिए एक बोली-पूर्व बैठक का आयोजन किया। बोलियों को जमा करने की अंतिम तिथि अंततः 25.05.2016 पर तय की गई थी।

6. निविदा शर्तों के अनुसार, प्रस्ताव तीन लिफाफों में किया जाना था, जिसे एक साथ प्रस्तुत किया जाना था, जैसा कि नीचे दिया गया हैः (i) पहला लिफाफा जिसे "प्रारंभिक फ़िल्टर-सह-योग्यता आवश्यकता बोली" कहा जाता है। (ii) दूसरा लिफाफा-"तकनीकी बोली" (iii) तीसरा लिफाफा-"मूल्य बोली"

7. निविदा आमंत्रित करने के नोटिस के जवाब में, अपीलार्थी और तीन अन्य नाम; (i) कंसोर्टियम ऑफ बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन जीएमबीएच; (ii) मेसर्स हुंडई रोटेम कंपनी (एचआरसी) और (iii) कंसोर्टियम ऑफ अल्सटॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड और अल्स्टॉम ट्रांसपोर्ट एसए ने निर्धारित तिथि तक अपनी बोलियों की पेशकश की।

8. निविदा प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार, पहले लिफाफे में दिए गए विवरणों के आधार पर पात्रता और योग्यता मानदंड का एक सकारात्मक निर्धारण "तकनीकी बोलियों" और "मूल्य बोलियों" वाले लिफाफों को खोलने के लिए पूर्व-आवश्यकता थी।

इससे पहले, बोली-पूर्व बैठकें आयोजित की जाती थीं, जैसा कि इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है, जिसमें विभिन्न भाग लेने वाले बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और बोलीदाताओं को निर्देशों के खंड संख्या 7 के अनुसार स्पष्टीकरण के लिए अपने प्रश्न प्रस्तुत किए, जिन पर तदनुसार विचार-विमर्श किया गया था। मांग के अनुसार स्पष्टीकरण दिए गए। अपीलार्थी ने कहा है कि उसने आवश्यकतानुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों वाले लिफाफे जमा किए हैं, जो सामान्य/विशिष्ट अनुभवों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। 25 मई 2016 को, जैसा कि निर्धारित किया गया था, चार बोलीदाताओं की "प्रारंभिक फ़िल्टर सह-योग्यता आवश्यकता बोली" वाले लिफाफे खोले गए और उसके बाद 9 जून 2016 को, प्रतिवादी ने 16 प्रश्न उठाए और अपीलार्थी से अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा।

9. अन्य प्रश्नों के अलावा, निविदा दस्तावेजों की धारा III के खंड 2.4 में निहित अनुभव के मानदंड से संबंधित प्रश्न। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नों और उत्तरों को विस्तार से बताना आवश्यक नहीं है, हमारे सामने उठाए गए केंद्रित तर्कों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि इसके बाद जल्द ही संदर्भित किया जाएगा। यह कहने के लिए पर्याप्त है, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया है, इसने प्रश्नों का पर्याप्त और पूरी तरह से उत्तर दिया और समकालीन अभिलेखों के साथ इसे पूरक किया ।

10. इसके बाद अपीलार्थी को पता चला कि 15.10.2016 पर प्रतिवादी ने अपनी "प्रारंभिक फ़िल्टर-सह-योग्यता आवश्यकता बोली" को अस्वीकार कर दिया था और इस प्रकार उसे निविदा प्रक्रिया में आगे की भागीदारी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद अपीलार्थी ने विभिन्न अभ्यावेदन और अनुरोध दायर करके प्रत्यर्थी निगम से असफल अनुरोध किया और कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया देने में विफल रहने के कारण कानूनी प्रक्रिया की शरण मांगी। इससे पहले, इसे उच्च न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा

दायर एक कैविएट आवेदन के साथ भी पेश किया गया था, जिसमें इसकी "प्रारंभिक फ़िल्टर-सह-योग्यता आवश्यकता बोली" की अस्वीकृति के बाद इसकी अयोग्यता का उल्लेख किया गया था।

11. प्रत्यर्थी-निगम, अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्ति उठाने के अलावा, आवश्यक पक्षों, यानी मैदान में जीवित निविदाकारों से गैर-याचिकाकर्ता का अनुरोध करते हुए, जोर देकर कहा कि परियोजना का वित्तपोषण गुजरात राज्य, भारत सरकार और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (संक्षेप में इसके बाद "जे. आई. सी. ए". के रूप में संदर्भित) के बजटीय संसाधनों के माध्यम से किया गया था। इसने यह भी उल्लेख किया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से, जनरल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, जो चार प्रसिद्ध कंपनियों का एक संघ है, को अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना-चरण ।, यानी हाथ में परियोजना से संबंधित कार्यों के लिए निविदा दस्तावेज तैयार करने, निविदा प्रस्तावों के मूल्यांकन आदि के संबंध में स्वतंत्र विशेषज्ञ पेशेवर सलाह प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया था। आम तौर पर 15.01.2016 पर निविदा आमंत्रित करने की सूचना जारी करने और अपीलकर्ता सहित चार बोलीदाताओं की भागीदारी से संबंधित तथ्यों को स्वीकार करते हुए, एम. ई. जी. ए. ने हालांकि स्पष्ट रूप से कहा कि बोली-पूर्व बैठकों के दौरान, एक स्पष्ट प्रश्न के जवाब में यह स्पष्ट किया गया था कि सहायक कंपनियों/समूह कंपनियों के अनुभव को किसी भी मामले में ध्यान में नहीं रखा जाएगा और यदि पक्ष इस तरह के अनुभव को गिनने के इच्छुक हैं, तो सहायक कंपनियों/समूह कंपनियों को एक संयुक्त उद्यम (जिसे इसके बाद "जे. वी". के रूप में भी संदर्भित किया जाएगा) या एक संघ का गठन करना होगा।

12. इसके अनुसार, भाग लेने वाले बोलीदाताओं की "प्रारंभिक फिल्टर सह-योग्यता आवश्यकता बोली" वाला पहला लिफाफा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में

खोला गया और अगली तारीख को, उन्हें मूल्यांकन और उसके संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सामान्य इंजीनियरिंग सलाहकार (संक्षेप में, इसके बाद "जी. ई. सी". के रूप में संदर्भित) को भेज दिया गया। जी. ई. सी. ने बदले में अपने दिनांकित पत्र 09.06.2016 के माध्यम से अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सिफारिश की गई थी कि संबंधित बोलीदाताओं से उसमें उल्लिखित बिंदुओं पर और स्पष्टीकरण मांगा जाए। इसके बाद प्रत्यर्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ अनुभव के पहलू पर अपीलार्थी को 16 प्रश्न भेजे, जैसा कि निविदा दस्तावेजों के मूल्यांकन और योग्यता मानदंड के खंड 2.4 में विचार किया गया है।

13. एम. ई. जी. ए. का यह रुख है कि अपीलार्थी ने मांगे गए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के बजाय, अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए, जिससे उसने अपने मूल प्रस्ताव को वस्तुतः संशोधित किया और अपनी तथाकथित सहायक कंपनियों के अनुभव से पीछे हटकर अपने अनुभव में कमी को पूरा करने का प्रयास किया। एम. ई. जी. ए. के अनुसार, अपीलार्थी की सहायक कंपनियों के रूप में, अलग कानूनी संस्थाओं के रूप में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा, प्रासंगिक निविदा मानदंडों के संदर्भ में उनके अनुभव को अपीलार्थी का अनुभव नहीं माना जा सकता क्योंकि उसने (अपीलार्थी) एक इकाई के रूप में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और न तो एक संयुक्त उद्यम के रूप में और न ही अपनी सहायक कंपनियों के साथ एक संघ के रूप में। हालाँकि अपने उत्तर में, एम. ई. जी. ए. ने अपीलार्थी के अकेले वित्तीय प्रमाणों के संबंध में भी अपनी आपत्ति व्यक्त की, लेकिन इसका उल्लेख करना अनावश्यक है, क्योंकि अपील में प्रतिद्वंद्वी आदान-प्रदान के दौरान इसका उल्लेख नहीं किया गया था।

14. एम. ई. जी. ए. के अनुसार, जी. ई. सी. ने अपने समक्ष पुनः रखे गए स्पष्टीकरणों के साथ बोली जी दस्तावेजों की जांच करने के बाद राय दी कि अपीलार्थी

को "निविदा दस्तावेज" के "मूल्यांकन और योग्यता मानदंड" से संबंधित धारा III के खंड 2.3 और 2.4 की आवश्यकताओं के प्रति गैर-उत्तरदायी पाया गया। वर्तमान उद्देश्य के लिए तत्काल संदर्भ के लिए खंड 2.4.1 और 2.4.2 के साथ जी. ई. सी. के निष्कर्षों के प्रासंगिक अंश को निकालना पर्याप्त होगा।

15. जी. ई. सी. की 28 जुलाई 2016 की इस रिपोर्ट को इसके बाद अपनी सहमति के लिए जे. आई. सी. ए. को भेज दिया गया और जे. आई. सी. ए. ने अपनी "कोई आपत्ति नहीं" दी और एम. ई. जी. ए. को शेष बोलीदाताओं की बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने और प्रक्रिया को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का निर्देश दिया।

16. तदनुसार, शेष तीन बोलीदाताओं को अपीलार्थी को खारिज करके "प्रारंभिक फिल्टर-सह-योग्यता आवश्यकता बोली" के चरण में योग्य घोषित किया गया था, क्योंकि वे "निविदा दस्तावेज" के "मूल्यांकन और योग्यता मानदंड" की धारा III के खंड 2.3 "वित्तीय स्थिति" और खंड 2.4 "अनुभव" में अनुध्यात आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे थे।

17. एम. ई. जी. ए. के अनुसार, अपीलार्थी को दिनांक 02.11.2016 वाले पत्र द्वारा उसकी अयोग्यता के बारे में सूचित किया गया था। इसने कहा है कि विवादित कार्रवाई सख्ती से निविदा मानदंडों के अनुसार है और वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी होने के कारण उपलब्ध नहीं है।

18. खंड 4.1 का उल्लेख करते हुए "निविदा दस्तावेज़" की धारा I में, अपीलकर्ता ने दोहराते हुए अनुरोध किया कि एम. ई. जी. ए. द्वारा निर्दिष्ट स्पष्टीकरण, जिसमें सहायक/समूह कंपनियों के अनुभव को संयुक्त उद्यम या संघ के अभाव में

शामिल नहीं किया गया है, एक पूरी तरह से अलग संदर्भ में एक प्रश्न के संबंध में था और इसकी बोली के लिए पूरी तरह से लागू नहीं था। अपीलार्थी के अनुसार, एक सहायक कंपनी द्वारा प्रत्यर्थी के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या वह अपनी मूल/समूह कंपनी के अनुभव का लाभ उठा सकती है और उसके जवाब में, यह समझाया गया था कि यदि कोई सहायक कंपनी मूल कंपनी के अनुभव का उपयोग करना चाहती है, तो मूल कंपनी या समूह कंपनी को उसके साथ एक संघ या एन बनाना चाहिए, जैसा भी मामला हो। अपीलार्थी ने इस प्रकार जोर देकर कहा कि उसने अपनी बोली प्रस्तुत की है, एक एकल इकाई के रूप में जो उसकी सहायक कंपनियों की धारक कंपनी है और अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के अनुभव का दावा किया है, स्पष्टीकरण जी. ई. सी. द्वारा भरोसा किया गया है और एम. ई. जी. ए. द्वारा इसे (अपीलार्थी) अयोग्य, त्रुटिपूर्ण के रूप में प्रक्रिया से बाहर करने के लिए कार्रवाई की गई है। यह आगे किए गए प्रश्नों पर अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ खड़ा रहा, यह तर्क देते हुए कि उन्होंने पर्याप्त रूप से उसी का उत्तर दिया और प्रदर्शित किया कि उनकी बोली आवश्यक निविदा शर्तों का पूरी तरह से अनुपालन कर रही थी।

19. उच्च न्यायालय ने "निविदा दस्तावेजों" की धारा III में निहित "मूल्यांकन और योग्यता मानदंड" के खंड 2.4 के विश्लेषण पर, अनुरोध किए गए तथ्यों और उनके समर्थन में दस्तावेजों पर स्थापित प्रतिद्वंद्वी अभिविन्यास की पृष्ठभूमि में, यह अभिनिर्धारित किया कि एक होल्डिंग कंपनी अपनी सहायक कंपनियों को नियंत्रित कर सकती है, जिनके पास आवश्यक अनुभव हो सकता है, क्योंकि सहायक कंपनियों को काम को निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं होगी, होल्डिंग कंपनी अपने अनुभव का लाभ नहीं उठा सकती है। यह विचार था कि चूंकि सहायक कंपनियों की पहचान होल्डिंग कंपनी से अलग होती है, इसलिए वे वास्तव में, होल्डिंग कंपनी की सहायक होने के कारण, अनुबंध के लिए एक पक्ष नहीं बनते हैं और किसी भी तरह से नियोक्ता

के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। इसने आकस्मिकता को अलग किया, जहां एक संयुक्त उद्यम या विभिन्न कंपनियों/व्यक्तियों का एक संघ बनाया जाता है, जिसका प्रत्येक घटक अनुबंध के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा। यह अनुमान था कि जे. वी. या संघ के इस तरह के गठन में, घटक कंपनियों के अनुभव का लाभ जे. वी. या संघ को उपलब्ध होगा, अन्यथा नहीं। संक्षेप में, इसने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया कि एकल आधार पर अपीलार्थी-निगम के पास अपेक्षित अनुभव नहीं था, जैसा कि निविदा शर्तों में निर्धारित किया गया था और इस तरह की कमी को पूरा करने के लिए अपनी सहायक कंपनियों के अनुभव का लाभ उठाना उसके लिए अनुज्ञेय नहीं था। अपीलार्थी और उसकी सहायक कंपनियों के बीच कार्य के निष्पादन में रुचि रखने वाले समुदाय के रूप में, अनुपस्थित था, इसलिए "मूल्यांकन और मानदंड की योग्यता" के खंड 2.4 के संदर्भ में अनुभव की कमी के कारण इसे अयोग्य घोषित करने की आक्षेपित कार्रवाई को इस प्रकार दोष नहीं दिया जा सकता था।

20. दोहराने के लिए, हमारे सामने पक्ष केवल इस पहलू पर हैं कि क्या अपीलकर्ता-निगम, "मूल्यांकन और मानदंड की योग्यता" के खंड 2.4 द्वारा निर्धारित अनुभव मानदंड को पूरा करने के लिए, अपनी सहायक कंपनियों के अनुभव का उपयोग "प्रारंभिक फ़िल्टर-सह-योग्यता आवश्यकता बोली" में अर्हता प्राप्त करने के लिए कर सकता है। कोई अन्य विवाद नहीं उठाया गया है। इस प्रकार वर्तमान जांच केवल इस पहलू तक ही सीमित होगी।

21. अपीलार्थी की ओर से यह आग्रह किया गया है कि एम. ई. जी. ए. की ओर से प्रस्तुत और उच्च न्यायालय द्वारा समर्थित "मूल्यांकन और मानदंड की योग्यता" के खंड 2.4 का स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से गलत है और खंड 4.1 के अक्षर और भावना के साथ पूरी तरह से असंगत है और अपीलार्थी के गठन और उसकी सहायक कंपनियों के

कार्यात्मक तंत्र से संबंधित रिकॉर्ड पर सामग्री की अवहेलना है और इस प्रकार बेतुका, मनमाना और तर्क की अवज्ञा के रूप में खारिज किया जा सकता है।

22. श्री सुंदरम ने तर्क दिया है कि अभिलेखों के सामने यह स्पष्ट है कि जिस प्रश्न के जवाब में, अपीलकर्ता-निगम द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यह था कि एक सहायक कंपनी/समूह कंपनी मूल कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम/संघ के सदस्य के रूप में बोली लगा सकती है, ताकि मूल/समूह कंपनी के अनुभव को ध्यान में रखा जा सके, एक सहायक कंपनी द्वारा मूल कंपनी/समूह कंपनी के अनुभव को सहायक कंपनी के अनुभव की योग्यता आवश्यकता को पूरा करने के लिए ध्यान में रखने की अनुमति देने के अनुरोध के साथ उठाया गया था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस प्रकार कहा है कि इस स्पष्टीकरण का अपीलकर्ता निगम पर कोई आवेदन नहीं था, जिसने एकल इकाई के रूप में अपनी बोली की पेशकश की थी, जैसा कि खंड 4,1 के तहत अनुमेय है और इसके प्रारंभिक और कार्यात्मक विन्यास को देखते हुए, यह कानूनी रूप से निविदा शर्तों को पूरा करने के लिए अपनी सहायक कंपनियों के अनुभव का लाभ उठाने का हकदार था। श्री सुंदरम के अनुसार, इस भारी कानूनी और तथ्यात्मक आधार पर अपीलकर्ता-निगम की अयोग्यता, इस न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए घोर मनमाना, अनुचित और अन्यायपूर्ण आह्वान है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने मुख्य रूप से न्यू होराइजन्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य-(1995) 1 एस. सी. सी. 478 में इस न्यायालय के फैसले पर अपने दावों के समर्थन में भरोसा किया।

23. प्रेरक खंडन में, प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा है कि चूंकि अपीलकर्ता तकनीकी पात्रता को पूरा करने में विफल रहा है, जो खंड 2.4.1 और 2.4.2 (ए), (बी) और (सी) में खंड 4.1 के दायरे और दायरे की सही व्याख्या पर, प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के साथ, उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई हस्तक्षेप

आवश्यक नहीं है। उन्होंने आग्रह किया कि जैसा कि स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी का अनुभव बिना उसकी सहायक कंपनियों के निविदा शर्तों द्वारा अनिवार्य अनुभव से कम है, एम. ई. जी. ए. की आक्षेपित कार्रवाई निर्विवाद है। श्री रोहतगी ने तर्क दिया कि केवल इसलिए कि अपीलार्थी की सहायक कंपनियां, जो अपने आप में अलग-अलग कानूनी संस्थाएं हैं, अनुभव के मामले में पात्र हैं, यह वास्तव में इसे (अपीलार्थी), मूल धारक कंपनी को पात्रता प्रदान नहीं करता है। उनके अनुसार, यदि प्रदान किया जाता है तो अनुबंध में एकल इकाई के रूप में आवेदन करने वाले अपीलार्थी, अपीलार्थी और एम. ई. जी. ए. और सहायक कंपनियों को सौदे में शामिल नहीं किया जाएगा, इतना कि उनके प्रदर्शन को सुरक्षित करना या ऐसी पहल की आवश्यकता होने की स्थिति में सहायक कंपनियों को जिम्मेदार ठहराना असंभव होगा। विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि जैसा कि खंड 4.1 के साथ-साथ विचाराधीन निविदा शर्तों के 2.4 से प्रदर्शित किया जा सकता है, एक सहायक कंपनी के अनुभव का लाभ केवल तभी लिया जा सकता है जब वह एक संयुक्त उद्यम या संघ का सदस्य हो। अपीलार्थी, एकल इकाई के रूप में अपनी बोली की पेशकश करने के बाद, एक होल्डिंग कंपनी के रूप में, वह निविदा शर्तों द्वारा निर्धारित अपने अनुभव में कमी की भरपाई करने के लिए अपनी सहायक कंपनियों के अनुभव का उपयोग करने का हकदार नहीं था। यह तर्क देते हुए कि न्यू होराइजन्स लिमिटेड (उपरोक्त) में कथन मामले के तथ्यों में अपीलार्थी के लिए कोई उपयोगी नहीं था, विद्वान वरिष्ठ वकील ने मुख्य रूप से इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय से समर्थन प्राप्त करने की मांग कीः

(1) एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य - 2016 (8) स्केल 765

(2) तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड बनाम सी. एस. ई. पी. डी. आई.-ट्रिश कंसोर्टियम-2016 (10) स्केल 69

(3) मोंटेकार्लो लिमिटेड बनाम एनटीपीसी लिमिटेड-2016 (10) स्केल 50

(4) कोर प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम बिहार राज्य-2011 (59) बीएलजेआर 183

(5) रोहडे और श्वार्ज जीएमबीएच एंड कंपनी केजी बनाम भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और अन्य - (2014) 207 डीएलटी 1

24. विवादास्पद दलीलों और उन पर आधारित दावों का विधिवत मूल्यांकन किया गया है। वर्तमान न्यायिक प्रयास का सामना करने वाला मुद्दा इस न्यायालय की जांच के दायरे में आया, हालांकि एक अन्य परियोजना के संदर्भ में, जिसमें अपीलकर्ता (प्रतिवादी संख्या 2) को अनुबंध दिया गया था, एक निर्णय जिसे 2017 के ई. सी. ए. संख्या 1353-1354-कंसोर्टियम ऑफ टीटागढ़ फ़ायरमा एडलर एस. पी. ए.-टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड बनाम नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (9 मई 2017 को तय किया गया) में बरकरार रखा गया था। संभावित निविदाओं के पात्रता मानदंडों से संबंधित खंड 4.1, जैसा कि उस निर्णय में शामिल है, निष्कर्षण के योग्य है ताकि इसके पाठ की खंड 4.1 के साथ तत्काल तुलना की जा सके जैसा कि इसमें शामिल है।

"4.1 एक बोलीदाता एक ऐसी फर्म हो सकती है जो एक निजी इकाई है, एक सरकारी स्वामित्व वाली इकाई-आईटीबी 43 के अधीन-या एक मौजूदा समझौते के तहत एक संयुक्त उद्यम (एन) के रूप में ऐसी संस्थाओं का कोई संयोजन या एक आशय पत्र द्वारा समर्थित इस तरह के समझौते में प्रवेश करने के इरादे से हो सकती है। एक संयुक्त उद्यम के मामले में, सभी सदस्य अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के

लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होंगे। जे. वी. एक ऐसे प्रतिनिधि को नामित करेगा जिसे बोली प्रक्रिया के दौरान जे. वी. के किसी भी और सभी सदस्यों के लिए और उनकी ओर से सभी व्यवसाय करने का अधिकार होगा और अनुबंध निष्पादन के दौरान जे. वी. को अनुबंध दिया जाता है। जब तक बी. डी. एस. में निर्दिष्ट नहीं किया गया है, तब तक जे. वी. में सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

25. "पात्रता मानदंड और सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी" पर आधारित उस अनुबंध के "निविदा दस्तावेजों" की धारा V ने आगे अनिवार्य किया कि बोली लगाने वाले जो सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम या संस्थान हैं, वे केवल तभी भाग ले सकते हैं जब वे यह स्थापित कर सकें कि वे (i) कानूनी और वित्तीय रूप से स्वायत्त हैं (ii) वाणिज्यिक कानून के तहत काम करते हैं। 26. नागपुर मेट्रो रेल परियोजना में "डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, परीक्षण, 69 यात्री रोलिंग स्टॉक (इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स) को चालू करने" और कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए अनुबंध का पुरस्कार, जिसे के. एफ. डब्ल्यू. डेवलपमेंट बैंक, जर्मनी द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में वित्त पोषित किया गया था, उच्च न्यायालय के समक्ष असफल रहा, एक निर्णय जिसे इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

27. अपीलार्थी की पात्रता के खिलाफ चुनौती के प्रमुख अंगों में से एक एकल इकाई के रूप में अनुभव की कमी थी और यह कि उसने अपनी पूर्ववर्ती मूल/मूल कंपनियों की सहायक कंपनियों के अनुभव के बल पर अपनी बोली प्रस्तुत की थी, विलय के बाद जहां से वह अस्तित्व में आया था, वह योग्यता मानदंडों के अनुसार पात्र नहीं था। वहाँ यह भी आग्रह किया गया था कि जब तक सहायक जे. वी. या कंसोर्टियम के घटक नहीं हैं, उनके अनुभव को होल्डिंग कंपनी के अनुभव का आकलन करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है और चूंकि स्वतंत्र आधार पर उसके पास

निर्धारित आवश्यक अनुभव नहीं था, इसलिए उसे केवल उसी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था।

28. तथ्यों के विस्तृत विश्लेषण के बाद, प्रासंगिक निविदा शर्तों के साथ-साथ इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा संयोजित कानून, अपीलार्थी-निगम की पात्रता के खिलाफ इस याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था।

29. समग्र दृष्टिकोण के उल्लेखनीय सादृश्य को देखते हुए, उसमें दर्ज प्रासंगिक टिप्पणियों को दोहराना और जांच के तहत मुद्दे पर निर्णायक प्रभाव डालना फायदेमंद होगा।

"24. मुख्य मुद्दा, जैसा कि हम समझते हैं, 1 "प्रत्यर्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 की तकनीकी बोली की स्वीकृति से संबंधित है और हमें आवश्यक शर्तों के संबंध में पात्रता मानदंडों की कसौटी पर पूरी तरह से संबोधित करने की आवश्यकता है। अन्य तकनीकी पहलुओं पर निर्णय, जैसा कि हमें वर्तमान में सलाह दी जाती है, विशेषज्ञों पर छोड़ दिया जाता है। हम उक्त क्षेत्र में प्रवेश करने का इरादा नहीं रखते हैं, हालांकि उक्त गणना पर एक कमजोर प्रयास किया गया है।

26. इस न्यायालय के समक्ष जो आग्रह किया गया है वह यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को एक इकाई के रूप में नहीं माना जा सकता था और किसी भी मामले में, यह अपनी सहायक कंपनियों के अनुभव का दावा नहीं कर सकता था क्योंकि इसकी सहायक कंपनियों के साथ कोई संघ या संयुक्त उद्यम नहीं बनाया गया था। होल्डिंग और सहायक कंपनियों के संबंधों के संबंध में, हमें बलवंत राय सलूजा (ऊपर) में अधिकारियों और रोहडे और श्वार्ज जीएमबीएच एंड कंपनी के. जी. (ऊपर) में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की भी सराहना की गई है। आवश्यक निवेदन यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 2

अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों सहित सहायक कंपनियों के मालिक के रूप में अपने अनुभव का दावा नहीं कर सकता है और "निगमित पर्दा उठाने" के सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता है, जैसा कि रेनुसागर पावर कंपनी (ऊपर) और भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम एस्कॉर्ट्स लिमिटेड और अन्य में निर्धारित किया गया है। यह भी तर्क दिया जाता है कि सरकारी स्वामित्व वाली इकाई के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक सरकारी स्वामित्व वाली इकाई सरकार से अलग है और उक्त उद्देश्य के लिए, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कोरबा और अन्य में प्राधिकरण से प्रेरणा ली गई है। यह भी आग्रह किया गया है कि जब निविदा में किसी विशेष कार्य को करने की आवश्यकता होती है, तो उसे उस विशिष्ट तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि कानून में परिकल्पना की गई है कि जहां किसी विशेष कार्य को एक निश्चित तरीके से करने की शक्ति दी गई है, तो उस कार्य को उस तरह से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। उपरोक्त उद्देश्य के लिए, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (उपरोक्त) में प्राधिकरण से प्रेरणा ली गई है जिसमें नजीर अहमद बनाम राजा सम्राट 3 पर निर्भरता रखी गई है।

27. एकल इकाई की अवधारणा और प्रथम प्रतिवादी द्वारा उपयोग किए गए विवेकाधिकार से निपटने के लिए आगे बढ़ने से पहले, हम न्यायालय की भूमिका से निपटने का इरादा रखते हैं जब न्यायालय द्वारा पात्रता मानदंडों को स्कैन करने और समझने की आवश्यकता होती है। मोंटेकार्लो लिमिटेड (ऊपर) में, न्यायालय ने टाटा सेल्युलर (ऊपर) का उल्लेख किया जिसमें कुछ सिद्धांत, अर्थात्, प्रशासनिक कार्रवाई पर न्यायिक प्रतिबंध की ओर इशारा करने वाली आधुनिक प्रवृत्ति; अदालत की भूमिका केवल उस तरीके की समीक्षा करना है जिसमें निर्णय लिया गया है; प्रशासनिक निर्णय को सही करने के लिए अदालत की ओर से विशेषज्ञता की कमी; सरकार को अनुबंध की स्वतंत्रता प्रदान करना जो एक प्रशासनिक क्षेत्र या अर्ध-प्रशासनिक क्षेत्र में काम

करने वाले प्रशासनिक निकाय के लिए जोड़ों में एक उचित खेल को एक आवश्यक सहवर्ती के रूप में मान्यता देता है, निर्धारित किया गया था। उक्त मामले में यह भी कहा गया था कि प्रशासनिक निर्णय का परीक्षण न केवल वेड्सबरी के तर्कसंगतता के सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा किया जाना चाहिए, बल्कि पक्षपात से प्रभावित या दुर्भावना से प्रेरित मनमानेपन से भी मुक्त होना चाहिए। दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि जगदीश मंडल (उपरोक्त) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि अनुबंध देने से संबंधित निर्णय प्रामाणिक है और जनहित में है, तो अदालतें न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप नहीं करेंगी, भले ही प्रक्रिया संबंधी विचलन या मूल्यांकन में त्रुटि या किसी निविदाकार के प्रति पूर्वाग्रह बनाया गया हो। मास्टर मरीन सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम मेटकाफ एंड हॉजकिन्सन (पी) लिमिटेड और अन्य 4, बी. एस. एन. में निर्णय। जोशी एंड संस लिमिटेड बनाम नायर कोल सर्विसेज लिमिटेड और अन्य 5 और मिशिगन रबर (इंडिया) लिमिटेड (उपरोक्त) को संदर्भित किया गया है। न्यायालय ने एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (उपरोक्त) के एक अंश का हवाला दिया जिसमें निविदा आवश्यकताओं की सराहना करने और मालिक या नियोक्ता द्वारा दस्तावेजों की व्याख्या करने के लिए रखी गई व्याख्या का सिद्धांत, जब तक कि दुर्भावनापूर्ण या समझ या प्रशंसा में विकृत रूप से प्रतिबिंबित नहीं होता है, संवैधानिक न्यायालयों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उक्त मामले में यह भी देखा गया है कि यह संभव है कि किसी परियोजना का मालिक या नियोक्ता निविदा दस्तावेजों की व्याख्या दे सकता है जो संवैधानिक न्यायालयों को स्वीकार्य नहीं है, लेकिन यह अपने आप में दी गई व्याख्या में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं है। उक्त प्राधिकारी का उल्लेख करने के बाद, इस प्रकार निर्णय दिया गया हैः

"24. हम कानून के उपरोक्त कथन से सम्मानपूर्वक सहमत हैं। हमारे पास ऐसा करने के कारण हैं। वर्तमान परिदृश्य में, निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं और अत्यधिक

जटिल तकनीकी विषयों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। इसके लिए काम की प्रकृति और इसके उद्देश्य की समझ और सराहना की आवश्यकता होती है। प्रतिस्पर्धी वाणिज्यिक क्षेत्र में यह आम जानकारी है कि निविदाएं आमंत्रित करने की सूचना के अनुसार तकनीकी बोलियों की तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाती है और कभी-कभी मालिक के संगठन से असंबद्ध लोगों से तीसरे पक्ष की सहायता ली जाती है। यह वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करता है। निविदाकर्ता की विशेषज्ञता और तकनीकी क्षमता और क्षमता का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए। वित्तीय मूल्यांकन के मामलों में सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जांचने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि तकनीकी क्षमता और वित्तीय व्यवहार्यता में उत्साह है और वे व्यवहार्य और यथार्थवादी हैं। एक बहु-आयामी जटिल दृष्टिकोण है; प्रकृति में अत्यधिक तकनीकी। जिन निविदाओं में सार्वजनिक धन को नीलामी के लिए रखा जाता है, वे एक अलग डिब्बे में खड़े होते हैं। जिस निविदा से हम संबंधित हैं, उसकी आवंटन के लिए किसी भी योजना से तुलना नहीं की जा सकती है। जिस क्षेत्र का हमने उल्लेख किया है, उसके लिए तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है। लागू किए गए मापदंड अलग-अलग हैं। इसका उद्देश्य निष्पादन और समय अनुसूची के पालन में उच्च स्तर की पूर्णता प्राप्त करना है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि ये निविदाएं न्यायिक समीक्षा की जांच से बच जाएंगी। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता होगी यदि दृष्टिकोण मनमाना है या दुर्भावनापूर्ण है या अपनाई गई प्रक्रिया किसी के पक्ष में है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए कि उक्त बीमारियों को दूर रखा गया है। लेकिन जहां कोई निर्णय लिया जाता है जो स्पष्ट रूप से निविदा दस्तावेज की भाषा के अनुरूप होता है या उप उस उद्देश्य को पूरा करता है जिसके लिए निविदा जारी की जाती है, अदालत को संयम के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अदालत द्वारा तकनीकी मूल्यांकन या तुलना अस्वीकार्य होगी। अन्य क्षेत्रों में

अनुबंध से संबंधित एक साधारण उपकरण को स्कैन करने और समझने के लिए लागू किए जाने वाले सिद्धांत को तकनीकी कार्यों और विशेष कौशल की आवश्यकता वाली परियोजनाओं से संबंधित निविदा दस्तावेजों की व्याख्या और सराहना करने से अलग तरीके से माना जाना चाहिए। मालिक को उद्देश्य को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए और स्वतंत्र रूप की अनुमति होनी चाहिए।

29. रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य मामले में, न्यायालय ने एशिया फाउंडेशन एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम ट्राफलगर हाउस कंस्ट्रक्शन (आई) लिमिटेड और अन्य मामलों में प्राधिकरण को संदर्भित किया, जिसमें यह देखा गया है कि यद्यपि न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत से इनकार नहीं किया जा सकता है, जहां तक सरकारी निकायों की संविदात्मक शक्तियों के प्रयोग का संबंध है, लेकिन इसका उद्देश्य मनमानेपन या पक्षपात को रोकना है और इसका प्रयोग व्यापक सार्वजनिक हित में किया जाता है या यदि यह अदालत के ध्यान में लाया जाता है कि अनुबंध देने के मामले में शक्ति का प्रयोग किसी भी संपार्श्विक उद्देश्य के लिए किया गया है। इसके बाद, अदालत ने रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (ऊपर) में इस प्रकार कहाः

"75....तत्काल मामले में, हम एन. आई. ए. में किसी भी संपार्श्विक उद्देश्य के लिए किसी भी मनमानेपन या पक्षपात या शक्ति के प्रयोग को समझने में असमर्थ हैं। इसके अभाव में, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। हम सोचते हैं कि राजस्व में वृद्धि और सेवा के दायरे में विस्तार के बाद यह एक विवेकपूर्ण निर्णय है।

और फिर सेः

"76. इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि जटिल नीलामी प्रक्रिया से संबंधित मामलों में, जिनके भारी वित्तीय निहितार्थ हैं, किसी भी धारणा के आधार पर न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप, जिसे विवेकपूर्ण माना जाता है या जिसे उचित माना जाता है, ऐसी स्थिति का कारण बन सकता है जो उचित नहीं है और जिसका अप्रत्याशित प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। इससे राजकोषीय असंतुलन की स्थिति पैदा होने की संभावना हो सकती है। हमारे विचार में, इस तरह की नीलामी में हस्तक्षेप सख्त जांच के आधार पर होना चाहिए जब एन. आई. ए. से शुरू होने वाली निर्णय लेने की प्रक्रिया अंत तक अप्रिय मनमानेपन या किसी भी बाहरी विचार की गंध आती है जो समझ में आता है।

32. प्रत्यर्थी संख्या 2, जैसा कि स्पष्ट है, चीन जनवादी गणराज्य के स्वामित्व वाली एक कंपनी है और इसलिए, यह एक सरकारी स्वामित्व वाली इकाई के रूप में बोली दस्तावेज के खंड 4 के दायरे में आती है। हम पहले ही निर्णय के पहले भाग में उक्त खंड को पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं, जैसा कि प्रथम प्रतिवादी द्वारा माना गया है, एक एकल इकाई अपने लिए बोली लगा सकती है और इसमें इसके घटक शामिल हो सकते हैं जो पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं और उन्हें परियोजना के संबंध में अनुभव हो सकता है। इसके अलावा, जैसा कि उक्त प्रत्यर्थी द्वारा समझा जाता है, जहां एकल या एकीकृत इकाई का दावा है कि विलय के परिणामस्वरूप, सभी सहायक अधिकार, देनदारियों, परिसंपत्तियों और दायित्वों के संबंध में अपने तत्काल नियंत्रण के तहत एक समरूप समूह बनाते हैं. ऐसे अधिकारों, परिसंपत्तियों और देनदारियों के मालिक के रूप में एकल इकाई की अखंडता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसे प्रभावी बनाया जाना चाहिए। दूसरे प्रत्यर्थी के पात्रता मानदंड का निर्णय करते समय, प्रथम प्रत्यर्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के संघ के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 164 को स्कैन किया है जो उस बोली के साथ प्रस्तुत किए गए हैं जिससे यह स्पष्ट है कि

प्रत्यर्थी संख्या 2 के निदेशक मंडल को सहायकों के लिए भी सभी आवश्यक और आवश्यक निर्णयों और कार्यों के निर्वहन का अधिकार और जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रथम प्रत्यर्थी के अनुसार, "सरकारी स्वामित्व वाली इकाई" शब्द में एक सरकारी स्वामित्व वाली इकाई और उसकी सहायक कंपनियां शामिल होंगी और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि स्थापित होने पर सरकार से संबंधित संस्थाओं की पहचान को सरकारी स्वामित्व वाली इकाई के रूप में माना जा सकता है और सहायक कंपनियों के माता-पिता द्वारा दावा किए गए अनुभव को ध्यान में रखा जा सकता है। प्रथम प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने "लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेटन वेल" के सिद्धांत या "पीएर्सिंग द वैल" के सिद्धांत की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है और उस संदर्भ में लिटिलवुड्स मेल ऑर्डर स्टोर्स, लिमिटेड बनाम मैकग्रेगर 6, डी. एच. एन. फूड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड और अन्य बनाम लंदन बरो ऑफ टॉवर हैमलेट्स 7 और हैरोल्ड होल्ड्सवर्थ एंड कंपनी पर निर्भरता रखी गई है। (वेकफील्ड) एल. डी. बनाम कैडीज़8. विद्वान वरिष्ठ वकील ने न्यू होराइजन्स लिमिटेड (उपरोक्त) में दोहराए गए रेनुसागर पावर कंपनी (उपर्युक्त) में बताए गए सिद्धांतों पर भी भरोसा किया है। प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से दायर लिखित निवेदन में, रेनुसागर पावर कंपनी (उपरोक्त) के प्रासंगिक पैराग्राफ को प्रचुर मात्रा में उद्धृत किया गया है। यह भी आग्रह किया जाता है कि वर्तमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगम अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से अपना व्यवसाय करें और इसलिए, एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं हो सकता है कि जब सहायक कंपनियों के अनुभव की बात की जाए तो मूलधन की पात्रता का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। श्री सुब्रमण्यम द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि धोखाधड़ी या कानूनी दायित्वों की चोरी के संदर्भ में, "पीएर्सिंग द वैल" या "लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेटन वेल" के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है, लेकिन उक्त सिद्धांत को वर्तमान प्रकृति के मामले में सहारा नहीं लिया जा सकता है।

33. प्रथम प्रत्यर्थी की संतुष्टि के संबंध में, हमारे समक्ष यह रेखांकित किया गया है कि उक्त प्रत्यर्थी ने बोली दस्तावेजों की पूरी तरह से जांच की थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 की क्षमता, अनुभव और विशेषज्ञता के बारे में खुद को संतुष्ट किया था और स्वतंत्र सामान्य सलाहकार द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 की तकनीकी योग्यता का गहन विश्लेषण किया गया है और प्रथम प्रत्यर्थी की मूल्यांकन और निविदा समिति की रिपोर्ट और के. एफ. डब्ल्यू. विकास बैंक से अनापत्ति भी प्राप्त हुई है। जर्मनी जो पूरी परियोजना का वित्तपोषण कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 के अनुभव का वर्णन करते हुए, प्रथम प्रतिवादी की ओर से दायर लिखित प्रस्तुति में यह कहा गया हैः

"36. रिकॉर्ड से यह और स्पष्ट है कि सबसे कम बोली लगाने वाले होने के अलावा, दुनिया भर में मेट्रो ट्रेनों की आपूर्ति में आर 2 का अनुभव याचिकाकर्ता के अनुभव से एक बड़े अंतर से अधिक है। जहाँ खंड 12 के लिए, आर 2 ने 594 मेट्रो कारों का आंकड़ा दिखाया है, याचिकाकर्ता ने केवल 72 कारों को दिखाया है; और खंड 12.1 के लिए जहाँ आर 2 ने 432 कारों को दिखाया है, याचिकाकर्ता ने फिर से केवल 72 कारों को दिखाया है। आर 2 का यह विशाल अनुभव परियोजना के लिए फायदेमंद होगा और जनहित को आगे बढ़ाएगा।

37. उस आर1 ने बिना किसी द्वेष या दुर्भावना के आर2 को अपनी 100% सहायक कंपनियों के साथ एक इकाई के रूप में माना है। खंड की यह समझ दोनों पक्षों के अंत में रही है। आर 1 और आर 2, जो अनुभव का उपयोग करके बोली लगाने और अपनी विभिन्न पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से अनुबंध को निष्पादित करने के लिए मूल कंपनी की पात्रता के अनुरूप थे।

38. यह कि अपनी 100% सहायक कंपनियों के साथ R2 का व्यवहार करने की R1 की उपरोक्त समझ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की समझ से समर्थित है,

जिसने इसी तरह, यदि समान नहीं है, तो शब्दबद्ध बोली-दस्तावेज पर R2 को निविदा/समझौता प्रदान किया है, जिसने वहाँ भी एक मूल कंपनी के रूप में बोली लगाई थी जो 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के अनुभव और निष्पादन का दावा करती थी।

39. इसके अलावा, मूल कंपनी को उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के साथ एक इकाई के रूप में मानने के लिए निविदा दस्तावेज में कोई स्पष्ट या निहित प्रतिबंध नहीं है। इसलिए, न्यायिक समीक्षा का दायरा परियोजना और जनता के सर्वोत्तम हित में आर 1 द्वारा लिए गए निर्णय पर निर्णय लेने में सीमित होना चाहिए।

40. यह तर्क, आर 1 द्वारा निविदा शर्तों की उपरोक्त समझ से परियोजना या याचिकाकर्ता सहित अन्य बोलीदाताओं के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है। यह विनम्रता से प्रस्तुत किया जाता है कि आर 2 ने सभी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा किया। बोली-दस्तावेज स्वयं एक संघ के रूप में बोली लगाने के लिए प्रदान किया गया था, और ऐसे मामले में किसी भी भौतिक शर्त को पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी, जिसे पूरा नहीं किया गया तो किसी भी पक्ष या परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, बोली-दस्तावेज की योजना ऐसी है कि यह स्वयं एक मूल कंपनी गारंटी प्रदान करती है। इस मूल कंपनी गारंटी प्रपत्र के अनुसार, सहायक कंपनी के विफल होने की स्थिति में एक मूल कंपनी को समझौते के तहत काम करना होगा। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियां अति-तकनीकी हैं और केवल एक बार असफल पाए जाने के बाद परियोजना को रोकने के लिए उठाई गई हैं।

34. जैसा कि ध्यान देने योग्य है, अभिलेख पर ऐसी सामग्री है कि प्रत्यर्थी संख्या 2, एक सरकारी कंपनी, सहायक कंपनियों और सहायक कंपनियों का मालिक है, जिसके पास अनुभव है। प्रथम प्रत्यर्थी, जैसा कि यह प्रतीत होता है, ने अपनी वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता को समझ और व्याख्या में लागू किया है जिसे संबंधित समिति और वित्तपोषण बैंक द्वारा सहमति दी गई है। हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि "सरकारी स्वामित्व वाली इकाई" की अवधारणा को संकीर्ण निर्माण नहीं माना जा सकता है। इसमें मालिक की संतुष्टि के अधीन अपनी सहायक कंपनियां शामिल होंगी। संयुक्त उद्यम या संघ के गठन की आवश्यकता नहीं है। तथ्य प्राप्त करने की स्थिति में, किसी भी प्रकार की विकृति, पूर्वाग्रह या दुर्भावना के अभाव में प्रथम प्रतिवादी द्वारा दी गई व्याख्या को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा लिया गया निर्णय, जैसा कि बोधगम्य है, वाणिज्यिक ज्ञान और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और यह जनहित के खिलाफ कोई तरीका नहीं है। इसलिए हम उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत हैं।

30. जो भी हो, उपरोक्त के बावजूद, संबोधित किए जाने वाले प्रश्न से संबंधित प्रासंगिक खंडों के महत्व की जांच और व्याख्या करना अपरिहार्य होगा। बोलीदाताओं को दिए गए निर्देशों की धारा 1 का खंड 4.1, जो "योग्य बोलीदाताओं" को परिभाषित करता है, निम्नलिखित शब्दों में हैः

"योग्य बोलीदाताः

4.1. एक बोलीदाता एक ऐसी फर्म हो सकती है जो एक एकल इकाई है या एक मौजूदा समझौते के तहत एक संयुक्त उद्यम (जेवी) के रूप में ऐसी संस्थाओं का कोई संयोजन है या इरादे के पत्र द्वारा समर्थित इस तरह के समझौते में प्रवेश करने के इरादे से हो सकती है। जे. वी. के मामले मेंः संघ का गठन स्वीकार्य है। निविदा की शर्त लागू

होती है। (क) सभी सदस्य अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे, और (ख) संयुक्त उद्यम एक प्रतिनिधि को नामित करेगा जिसे बोली प्रक्रिया के दौरान संयुक्त उद्यम के किसी भी और सभी सदस्यों के लिए और उनकी ओर से सभी व्यवसाय करने का अधिकार होगा और यदि अनुबंध निष्पादन के दौरान एन को अनुबंध दिया जाता है।

31. उसी धारा के खंड 7.1 का एक प्रासंगिक उद्धरण, जो बोली दस्तावेजों के स्पष्टीकरण के लिए प्रदान करता है, बोली-पूर्व बैठक के लिए साइट पर जाएँ, नीचे प्रस्तुत किया गया हैः

"एक बोलीदाता जिसे बोली दस्तावेजों के किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, वह नियोक्ता से बी. डी. एस. में निर्दिष्ट नियोक्ता के पते पर संपर्क करेगा या बोली-पूर्व बैठक के दौरान अपनी पूछताछ करेगा यदि ITB.7.4 के अनुसार प्रदान किया गया है।

32. "मूल्यांकन और मानदंड की योग्यता" के खंड 2.4.1 और 2.4.2 (ए) और (बी), धारा III को भी नीचे निकाला गया हैः

"सामान्य अनुभव (खंड 2.4.1)

1 जनवरी, 2006 से शुरू होने वाले कम से कम पिछले दस वर्षों के लिए प्रमुख ठेकेदार (एकल इकाई या संयुक्त उद्यम सदस्य), उप-ठेकेदार या प्रबंधन ठेकेदार की भूमिका में अनुभव।

विशिष्ट अनुभव खंड 2.4.2

(ए) न्यूनतम दो (2) समान अनुबंध जो 1 जनवरी, 2006 और बोली जमा करने की समय सीमा के बीच एक प्रमुख ठेकेदार (एकल इकाई या संयुक्त उद्यम सदस्य) के रूप में संतोषजनक और पर्याप्त रूप से पूरे किए गए हैं।

विशिष्ट अनुभव (2.4.2 (बी)

वाहन डिजाइन, इंटरफेस (अन्य नामित ठेकेदारों जैसे सिग्नलिंग, ट्रैक ट्रैक्शन, आदि के साथ) के लिए प्रमुख ठेकेदार (एकल इकाई या जेवी सदस्य) की भूमिका में अनुबंधों के तहत अनुभव।

1 जनवरी, 2006 और बोली जमा करने की समय सीमा के बीच तीन चरण कर्षण प्रणोदन प्रणाली ए. टी. पी./ए. टी. ओ. प्रणाली आदि सहित समान सुविधाओं के साथ या तो बिना इस्पात या एल्यूमीनियम से बनी कुल 150 मेट्रो (यानी एम. आर. टी., एल. आर. टी., उप-शहरी रेलवे या उच्च गति वाली रेलवे) कारों की असेंबली और आपूर्ति, परीक्षण और कमीशनिंग।

और

उपरोक्त आपूर्ति की गई और चालू की गई 150 या उससे अधिक कारों में से कम से कम कुल 75 मेट्रो (यानी एम. आर. टी., एल. आर. टी., उप-शहरी रेलवे या उच्च गति वाली रेलवे) कारों की आपूर्ति की गई है और कम से कम पांच वर्षों तक संतोषजनक राजस्व संचालन में हैंः दोनों मूल देश के बाहर या भारत में कम से कम 1 (एक) देश में।

33. यह रिकॉर्ड की बात है कि 16.03.2016 और 30.04.2016 के बीच, बोलीदाताओं के साथ बोली-पूर्व बैठकों के दौरान, उनके द्वारा कुछ प्रश्न उठाए गए थे, जिन पर मेगा द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया था। अभिलेखों से उपलब्ध निम्नलिखित प्रश्न और स्पष्टीकरण जो पहले से ही प्रासंगिक हैं,

34. खंड 4.1 के एक सादे पठन से पता चलता है कि एक बोलीदाता एक एकल इकाई या ऐसी संस्थाओं का एक संयोजन हो सकता है जो एक जे. वी. या एक संघ के रूप में एक मौजूदा समझौते के तहत या एक आशय पत्र द्वारा समर्थित ऐसे समझौते में प्रवेश करने के इरादे से हो सकता है। इस प्रकार एक एकल इकाई को सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए एक वैध बोलीदाता माना गया है।

35. परियोजना के परिमाण के साथ-साथ उसके गुणवत्ता निष्पादन के लिए आवश्यक अनुभव और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए, पहली जगह पर, किसी सरकारी स्वामित्व वाली इकाई को उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के साथ इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य होने का अनुमान लगाने का कोई औचित्य नहीं है। हमारी समझ में, एक एकल इकाई में निश्चित रूप से ऐसी सरकारी स्वामित्व वाली इकाई के साथ-साथ इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां भी शामिल होंगी। यह एक सार्वजनिक परियोजना के समय पर और गुणवत्ता निष्पादन के समग्र हित में प्रतिस्पर्धी मूल्य और क्षमताओं के साथ संस्थाओं की व्यापक आधारित भागीदारी की अन्यथा अनिवार्य सुविधा की कसौटी पर अधिक है।

36. जैसा कि तीतागढ़ फ़ायरमा एडलर एस. पी. ए. (उपरोक्त) के संघ में दर्ज है, अपीलकर्ता-निगम एक सरकारी स्वामित्व वाली इकाई है जिसकी पूर्ण स्वामित्व वाली

सहायक कंपनियां एक समग्र इकाई के रूप में हैं, इतना कि इसके किसी भी घटक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में से किसी एक के अनुभव को इसके अनुभव के रूप में माना जा सकता है। यह घोषणा की गई कि याचिकाकर्ता (प्रतिवादी संख्या 2 उसमें) एक सरकारी कंपनी थी और उसकी सहायक कंपनियों का मालिक था और "सरकार की अपनी इकाई" की अवधारणा को एक संकीर्ण संरचना नहीं दी जा सकती थी ताकि उसकी सहायक कंपनियों को उनके अनुभव से अलग किया जा सके और अपनी सहायक कंपनियों के अनुभव का लाभ उठाने के लिए सरकार की अपनी इकाई के लिए एक संयुक्त उद्यम और संघ के गठन की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह भी रेखांकित किया गया कि याचिकाकर्ता (प्रतिवादी संख्या 2) की स्वीकृति, उसे दिए गए कार्य के संदर्भ में, समग्र वाणिज्यिक अवधारणा और विशेषज्ञता की मांग को ध्यान में रखते हुए, जनहित के अनुरूप थी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मेसर्स सी. एन. आर. निगम और मेसर्स सी. एस. आर. निगम के विलय की प्रक्रिया और अपीलार्थी-निगम में रूपांतरण के लिए उनकी सहायक कंपनियों के साथ इसका एकीकरण सह-मूल्यांकन अभिलेखों द्वारा किया जाता है।

37. मामले के उस दृष्टिकोण में, वर्तमान निविदा प्रक्रिया में एकल इकाई बोलीदाता के रूप में अपीलकर्ता-निगम की स्थिति और अधिकार, जैसा कि पहले से ही टीटागढ़ फ़ायरमा एडलर एस. पी. ए. (ऊपर) के संघ में निर्णय लिया गया है, सरल तर्क और सादृश्य के मानदंड से भी उपलब्ध होंगे। खंड 4 में "सरकारी स्वामित्व वाली इकाई" शब्दों की अनुपस्थिति, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का कोई परिणाम नहीं है। प्रत्यर्थी की यह दलील कि निविदा की शर्तें शामिल हैं, उसके समग्र वैचारिक ढांचे में एक अलग दृष्टिकोण की मांग करती है, अनुनय का अभाव है। उल्लेखनीय है कि कंसोर्टियम ऑफ टीटागढ़ फ़ायरमा एडलर एस. पी. ए. (उपरोक्त) में शामिल खंड 4.1 में, "सरकारी स्वामित्व वाली इकाई" को एक संयुक्त उद्यम (जे. वी.) के रूप में "निजी

इकाई" और "ऐसी संस्थाओं के किसी भी संयोजन" के विपरीत बोली लगाने वालों में से एक के रूप में माना गया था। वर्तमान खंड में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "एकल इकाई" होने के कारण, समझ में आता है कि इसमें एक निजी के साथ-साथ एक सरकारी स्वामित्व वाली इकाई भी शामिल है। एक इकाई के रूप में परिकल्पित इकाई इस प्रकार एक जेवी या एक संघ के रूप में किसी भी संयोजन या गठन से स्वतंत्र है और इस प्रकार एक अभिन्न और समग्र समग्र के रूप में कल्पना की जाती है। इस तरह के तार्किक आधार में, अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के साथ एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी को एकल इकाई के रूप में समझा जाना चाहिए, जो निविदा शर्तों के खंड 4 के संदर्भ में बोली लगाने के लिए पात्र है और इसे एकल, सुसंगत और सजातीय अस्तित्व के रूप में माना जाना चाहिए, न कि एक असंबद्ध गठन के रूप में।

38. विवाद से संबंधित प्रश्न और स्पष्टीकरण, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, हमारी समझ में भी, किसी भी तरह से एम. ई. जी. ए. की दलील की पुष्टि नहीं करते हैं। अपीलार्थी की बोली की अस्वीकृति का आधार मुख्य रूप से क्रम संख्या 50 पर प्रश्न का स्पष्टीकरण है। यह पेटेंट है कि यह एक सहायक कंपनी द्वारा अपने लाभ के लिए मूल कंपनी/समूह कंपनियों के अनुभव को उसके संबंध में योग्यता की आवश्यकता को पूरा करने की अनुमति देने के लिए किए गए प्रश्न के जवाब में था। इस संदर्भ में यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि सहायक कंपनी/समूह कंपनियाँ मूल कंपनी के साथ जे. वी./कंसोर्टियम सदस्य के रूप में बोली लगा सकती हैं, ताकि मूल/समूह कंपनी के अनुभव को ध्यान में रखा जा सके। इस स्पष्टीकरण को बढ़ाया गया और अपीलार्थी के खंड संख्या 2.4 के संबंध में लागू किया गया। 1, 2.4.2 (ए), 2.4.2 (बी) और 2.4.2 (सी) इसे इस आधार पर अयोग्य ठहराने के लिए कि अकेले आधार पर, यह निर्धारित अनुभव में कमी थी और यह कि यह अपनी सहायक कंपनियों के अनुभव का लाभ नहीं

उठा सकता था। जैसा कि अपीलार्थी की ओर से उचित रूप से तर्क दिया गया है, हमारा विचार है कि इस स्पष्टीकरण का उसके मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है और इसलिए, इस आधार पर इसे अयोग्य घोषित करने का निर्णय स्पष्ट रूप से मनमाना, भेदभावपूर्ण, अनुचित, अतार्किक और गैर-पारदर्शी है, इस प्रकार इसे अपरिवर्तनीय रूप से अवैध, अन्यायपूर्ण और अनुचित बनाता है। प्रत्यर्थी द्वारा अपने उत्तर शपथ पत्र में किए गए सुधार का प्रयास अभिलेखों द्वारा गलत है और अस्वीकार्य है। निविदा शर्तों के प्रासंगिक खंडों का कोई अन्य दृष्टिकोण या स्पष्टीकरण बिल्कुल भी संभव नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत और उच्च न्यायालय द्वारा प्रासंगिक ढांचे में समर्थित व्याख्या इस प्रकार स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य और बेतुकी है।

39. न केवल अपीलार्थी, जैसा कि अभिलेख गवाही देता है, ने मांगे गए स्पष्टीकरणों पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, बल्कि सरकारी स्वामित्व वाले निगम के रूप में इसकी स्थिति को किसी भी तरह से एम. ई. जी. ए. द्वारा विवादित नहीं किया गया है। इसके अलावा, इसकी प्रदर्शित संरचनात्मक अखंडता और सभी परिणामी कानूनी निहितार्थों के साथ इसकी सहायक कंपनियों की कार्यात्मक एकता के बावजूद, एम. ई. जी. ए. की यह आशंका कि अपीलार्थी की सहायक कंपनियां, यदि आवश्यकता पड़ी तो, परियोजना के निष्पादन के लिए उपलब्ध नहीं होंगी, कम से कम कहने के लिए, अनुबंध का एक पक्ष नहीं होना, अटकलबाजी, निराधार, दूरगामी और तर्क और तर्क में अभाव है। क्या अपीलार्थी की सहायक कंपनियां कार्य के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होंगी, यह अपीलार्थी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की संरचनात्मक विशिष्टताओं और कार्यात्मक गतिशीलता से स्पष्ट होता है, जैसा कि टीटागढ़ फ़ायरमा एडलर एस. पी. ए. (ऊपर) के कंसोर्टियम में सकारात्मक रूप में देखा गया है और इसमें आगे विस्तार की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त निर्णय में बार में उद्धृत निर्णयों के फोरेंसिक विश्लेषण के बावजूद, इसे वापस लेना भी आवश्यक नहीं है।

40. उपरोक्त निर्धारण के मद्देनजर, खंड 2.4 के संदर्भ में अनुभव की कमी के आधार पर अपीलार्थी की आक्षेपित अयोग्यता कानून में और तथ्यों के घोर रूप से अवैध, मनमाना और विकृत होने पर टिकाऊ नहीं है। एक परिणाम के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को भी चुनौती दी जाती है। उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए निविदा प्रक्रिया को इसके बाद उसके नियमों और शर्तों के अनुसार और कानून के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा और यथासंभव शीघ्रता से इसके तार्किक अंत तक ले जाया जाएगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान निर्णय केवल "निविदा दस्तावेज" की "पात्रता और योग्यता मानदंड" के खंड 2.4 के आधार पर अनुभव के आधार पर अपीलार्थी की अयोग्यता के मुद्दे तक ही सीमित है और कोई अन्य पहलू नहीं है। अपील की अनुमति है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील को मंजूरी दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक सपना राजपुरोहित की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।